



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1841]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 7, 2010/भाद्र 16, 1932

No. 1841]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 7, 2010/BHADRA 16, 1932

श्रम और रोजगार मंत्रालय

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

अधिसूचना

NOTIFICATION

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 2010

New Delhi, the 7th September, 2010

का.आ. 2185(अ).—केन्द्रीय सरकार संतुष्ट हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ढ) के उप-खंड (vi) के उपबन्धों के अनुसरण में भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 17 मार्च, 2010 द्वारा बैंक नोट मुद्रणालय देवास, जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 22 के अंतर्गत निर्दिष्ट किया गया है को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए दिनांक 17 मार्च, 2010 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था;

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है;

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उप-खण्ड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए दिनांक 17 सितम्बर, 2010 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस-11017/1/2006-आईआर (पीएल)]

रवि माथुर, अपर सचिव

S.O. 2185(E).—Whereas the Central Government having been satisfied that the public interest so requires that in pursuance of the provisions of sub-clause (vi) of clause (n) of Section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), declared by the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment, dated 17th March, 2010 the service engaged in Bank Note Press, Dewas which is conered by item 22 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) to be a Public Utility Service for the purpose of the said Act, for a period of six months from 17th March, 2010.

And whereas, the Central Government is of opinion that public interest requires the extension of the said period by a further period of six months.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the provisio to sub-clause (vi) of clause (n) of Section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the said industry to be a Public Utility Service for the purposes of the said Act, for a period of six months from 17th September, 2010.

[F.No.S-11017/1/2006-IR(PL)]

RAVI MATHUR, Addl. Secy.